

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,  
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2

देहरादून : दिनांक : 21 अगस्त, 2008

विषय: भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में कम्प्यूटर कक्षों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 में केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 15-दो(8)/XXXVI(2)/08-219-एक(1)/05, दिनांक 30.6.2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में कम्प्यूटर कक्षों के निर्माण हेतु निम्न तालिका में अंकित प्रस्तावों के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कुल धनराशि रु० 14,10,000/- (चौदह लाख दस हजार रुपये मात्र) में से स्तम्भ-6 में अंकित केन्द्रांश की कुल धनराशि रुपये 7,05,000/- (सात लाख पांच हजार रुपये मात्र) को वित्तीय वर्ष 2008-2009 में व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्य	आगणित धनराशि	टी०ए०सी०द्वारा संस्तुत धनराशि	राज्यांश	केन्द्रांश
1	2	3	4	5	6
1.	न्यायालय पुरोला उत्तरकाशी में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	2.08	1.77	0.885	0.885
2.	कीर्तिनगर स्थित न्यायालय में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	3.25	2.70	1.35	1.35
3.	नरेन्द्रनगर स्थित न्यायालय में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	3.25	2.70	1.35	1.35
4.	जिला न्यायालय पौड़ी गढ़वाल परिसर में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	4.88	4.59	2.295	2.295
5.	जिला न्यायालय पिथौरागढ़ के कम्प्यूटरीकरण हेतु नये कक्षों का निर्माण	2.63	2.34	1.17	1.17
	<b>कुल योग</b>		<b>14.10</b>	<b>7.05</b>	<b>7.05</b>

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाय ।
- (3) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकृत विभाग/सक्षम अधिकारी से नक्शा पास कराया जाना आवश्यक है ।
- (4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी राशि स्वीकृत की गयी है ।
- (5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
- (6) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय ।

- (7) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय ।
- (8) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।
- (10) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रुल्स, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्चोरमेंट) नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (11) निर्माण इकाई कार्य 03 माह में समाप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं हस्तान्तरण प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
- (12) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.5.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2009 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के आयोजनागत पक्ष में लेखा-शीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60 -अन्य भवन-051-निर्माण-03-न्यायिक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण-00-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-264-एनपी/XXVII(5)/2008, दिनांक 19.8.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

( आर०डी०पालीवाल )  
सचिव ।

संख्या-25-दो(8)/XXXVI(2)/08-219-एक(1)/05-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 3- श्री रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय(न्याय विभाग), जैसलमेर हाउस, 26 मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया केन्द्रांश की धनराशि रु० 7.05 लाख उत्तराखण्ड राज्य के न्याय विभाग के पक्ष में शीघ्र अवमुक्त करने का कष्ट करें ।
- 4- जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ ।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/उत्तरकाशी/टिहरी गढ़वाल/पौड़ी गढ़वाल/पिथौरागढ़ ।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला(उत्तरकाशी)/नई टिहरी (बौराडी)/पिथौरागढ़ ।
- 7- नियोजन विभाग, वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
- 8- एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

( आलोक कुमार वर्मा )  
अपर सचिव ।